



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1946 (श0)  
(सं0 पटना 509) पटना, बुधवार, 12 जून 2024

सं० 27/आरोप-01-101/2021 सा0प्र0-5998  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प  
12 अप्रील 2024

श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 701/2011, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी बन्दोवस्त, खगड़िया-सह-जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5011 दिनांक-24.11.2021 एवं पत्रांक-1583 दिनांक-01.04.2022 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ।

2. श्री कुमार के विरुद्ध इनके पदस्थापन अवधि में मेसर्स माँ लक्ष्मी राईस मिल, बेगूसराय से बैंक गारंटी नहीं ली गयी तथा Deed of Pledge नियमानुकूल नहीं रहने के कारण प्रमादी मिलरों के द्वारा जमा नहीं किये गये सी0एम0आर0 समतूल्य राशि की वसूली नहीं की गयी, जिसके कारण निगम को मो0-38,78,734.00 (अड़तीस लाख अठत्तर हजार सात सौ चौतीस) रुपये की आर्थिक क्षति हुई है।

3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-9586 दिनांक-15.06.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण दिनांक-17.11.2022 प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार द्वारा स्वयं के ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया गया है।

4. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1876 दिनांक 25.01.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

5. आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 10547 दिनांक 30.12.2023 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर विभागीय पत्रांक 1131 दिनांक 19.01.2024 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा पत्रांक 136 दिनांक 07.02.2024 द्वारा अपना बचाव अभिकथन समर्पित किया गया।

6. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/बचाव बयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Deed of Pledge में वर्णित भूखण्डों का मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित मिलरों से प्राप्त किया गया था, जिसकी सत्यता की जांच तत्समय आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं कर एकरारनामा किया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रक्रियागत चूक हुई है तथा इस आरोप प्रकरण में वित्तीय अनियमितता भी परिलक्षित है। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथा संशोधित नियमावली, 2005 के नियम, 14 (iv) के संगत प्रावधानों के तहत दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापक 4993 दिनांक 21.03.2024 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथा संशोधित नियमावली, 2005 के नियम, 14 (iv) के संगत प्रावधानों के तहत दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी।

7. श्री कुमार द्वारा स्वयं पर अधिरोपित दंड के विरुद्ध एक पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अभिकथित है कि:-

(i) जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के अतिरिक्त प्रभार में वे मात्र 3 माह रहे थे। प्रभार अवधि में प्रमादी मिलर मेसर्स माँ लक्ष्मी राईस मिल, बेगूसराय के द्वारा कुल बकाया राशि मो0-38,78,734/- (अड़तीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ चौतीस) रुपये में से मात्र मो0-12,00,000/- (बारह लाख) रुपये का ही भुगतान किया गया। उक्त मिलर के पास कुल मो0-26,78,734 /- रुपये बकाया है। प्रमादी मिलर से बैंक गारंटी नहीं लिया गया था परंतु मिलर से Deed of Pledge प्राप्त कर उसके साथ एकरारनामा किया गया था।

(ii) Deed of Pledge में वर्णित भूखण्डों का मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित मिलर से प्राप्त किया गया था जो तत्कालीन अंचलाधिकारी, तेघड़ा द्वारा निर्गत किया गया था। इसकी सत्यता की जांच अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा से करायी गयी। उनके जांच प्रतिवेदन के अनुसार अंचलाधिकारी, तेघड़ा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि उक्त प्रमाण पत्र पर अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा कार्यालय के प्रमाण पत्र पंजी की खोज करायी गयी, किन्तु पंजी उपलब्ध नहीं हो पायी है।

(iii) अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा के इसी प्रतिवेदन के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा मान लिया गया कि भूखंड से संबंधित मूल्यांकन प्रतिवेदन सही नहीं रहने के कारण किया गया एकरारनामा त्रुटिपूर्ण है। उक्त मामले में नीलामपत्र वाद सं0-01/14-15 दायर किया गया। प्रमादी मिलर के विरुद्ध प्राथमिकी कांड सं0-812/15 चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज है तथा प्राथमिकी के विरुद्ध मामला स्थानीय कोर्ट व थाना में विचाराधीन है।

(iv) विभागीय कार्रवाई लंबे अर्से के बाद तकरीबन दस वर्षों के बाद संचालित की गयी तथा इस लंबे वक्त में परवर्ती विभागीय पदाधिकारी/निगम अगर चाहते तो उक्त प्रमादी मिलर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए राशि की

वसूली कर सकते थे। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में किसी भी अभिलेखों की प्रदर्शों का चिन्हित नहीं किया गया और न ही संबंधित अभिलेखों के ऑथर/राईटर को गवाह बनाया गया और न ही किसी गवाहों से प्रतिपरीक्षण कराया गया है।

8. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में अधिरोपित धान को मिलिंग हेतु मेसर्स माँ लक्ष्मी राईस मिल, बेगूसराय के साथ धान मिलिंग हेतु दिनांक 05.03.2013 को एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के तहत मिलों को आपूर्ति धान के समुत्पन्न से बैंक गारंटी नहीं ली गयी तथा नियमानुकूल Deed of Pledge नहीं किया गया। संबंधित Deed of Pledge से ज्ञात होता है कि प्रमादी मिलर के पिता श्री गुलो महतो के नाम से धारित भू-खण्ड का सही विवरण Deed of Pledge में दर्ज नहीं है। भू-खण्डों का प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, तेघड़ा से निर्गत दर्शाया गया था, जबकि मूल्यांकन प्रतिवेदन का सत्यापन कराने से ज्ञात हुआ कि संबंधित मूल्यांकन प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, तेघड़ा से निर्गत नहीं है। श्री कुमार द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित अंचलाधिकारी से सत्यापित कराये बिना ही एकरारनामा किया गया था, जिसके कारण निगम को आर्थिक क्षति हुई। जांच प्रतिवेदन के आदेशफलक से विदित होता है कि श्री कुमार को बचाव का पूरा अवसर दिया गया तथा सभी दस्तावेज उपलब्ध कराये गये।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4993 दिनांक 21.03.2024 द्वारा अधिरोपित शास्ति यथा दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

9. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 701/2011, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी बन्दोवस्त, खगड़िया-सह-जिला प्रबंधक के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4993 दिनांक 21.03.2024 द्वारा अधिरोपित शास्ति यथा दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति को यथावत रखा जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रविन्द्र नाथ चौधरी,  
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 509-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>